

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 25/22

GCMS NO 2022/23

1. ओमप्रकाश पुत्र रामकरण जाति मीना निवासी मलारना चौड तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर
2. कमलेश पुत्र रामकरण जाति मीना निवासी मलारना चौड तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर

अपीलांत

बनाम

1. भीमसिंह पुत्र रामकिशन जाति मीना निवासी मलारना चौड तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर
2. दीपक पुत्र रामकिशन जाति मीना निवासी मलारना चौड तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर
3. तहसीलदार तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर

रैस्यो0

अपील विरुद्ध मु0नं0 61/19 निर्णय व डिक्री दिनांक 13.1.22 न्यायालय उपजिला कलक्टर, मलारना डूंगर)

अभिभाषक अपीला0 श्री हरिमोहन जाट

अभिभाषक रैस्यो0 श्री अशोक कुमार साहू

दिनांक 02.12.2024

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 13.1.22 न्यायालय उपजिला कलक्टर, मलारना डूंगर पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांत/वादी द्वारा एक वाद पत्र स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 92 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के व्यक्ति है। सजरा खानदान अनुसार रामकरण एवं रामकिशन दोनो भाई थे। रामकरण के पुत्र हरिराम,ओमप्रकाश,कमलेश है। जो वादीगण है। रामकिशन के पुत्र भीमसिंह व दीपक है। जो प्रतिवादीगण है। स्व0रामकिशन व रामकरण ने अपनी पैतृक सम्पति आराजीयात को आपसी सहमति से दिनांक 23.5.02 को बराबर कर बांट लिया। उसी अनुसार काबिज होकर काश्त करते रहे। इसी अनुसार कब्जे शुदा बाडे का भी बंटवारा कर लिया। जिसके अनुसार पीपलीवाला बाडा , रामगोपाल के पास बाला वाडा वादीगण के पिता रामकरण के हिस्से मे आया एवं दूसरा बाडा मोहनलाल के पास वाला प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता रामकिशन के हिस्से मे आया। जब तक दोनो भाई जिवित थे तब तक कोई विवाद नही हुआ। प्रतिवादीगण के पिता रामकिशन की मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण के मन मे बदनियती आ गई और उनके द्वारा वादीगण के हिस्से मे आये वाडे पर अवैध रूप से कब्जा करना शुरू कर दिया। वादीगण का वाडा आंराजी ख0न0 5547 रकबा 0.99 है0 किस्म गैर कृषि केन खरडा मे स्थित है। प्रतिवादीगण ने अपने पिता के हिस्से मे आये वाडे पर निर्माण करवा के बाद

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

वादीगण के हिस्से में आए बाड़े पर लठठ के जोर पर अवैध रूप से निर्माण करना शुरू कर दिया। जिसका विरोध करने पर झगड़े पर आमादा हो गये तथा वादीगण के परिवार के साथ मारपीट की गई। वादीगण अपने पूर्वजों के समय से ही विवादित स्थल को बाड़े के रूप में उपयोग करते आ रहे हैं। वादीगण के इस कब्जे शुदा भूमि पर प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का अवैध पक्का निर्माण करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः दावा वादीगण इस आशय का विरुद्ध प्रतिवादी फरमाया जावे कि प्रतिवादी न० 1 व 2 को वादीगण के कब्जे शुदा भूमि बाड़ा ख०न० 5547 रकबा 0.99 है० ग्राम मलारना चौड में किये गये अवैध अतिक्रमण एवं निर्माण से बेदखल कर निर्माण का ध्वस्त कराया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीगण के बाड़े ख०न० 5547 के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर वादीगण/अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पों को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषकगण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य का सही विवेचन नहीं किया है। तनकी संख्या 1 के संबंध में साक्ष्य पटवारी हल्का की रिपोर्ट से वादी का कथन सिद्ध है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 वादी के विरुद्ध तय की गई है। तनकी संख्या 2 को सिद्ध मानते हुए प्रतिवादी का कब्जा अवैध माना है फिर भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध कोई आदेश न देकर अहम भूल की है। तनकी संख्या 3 को निर्णित करते समय अधिनस्थ न्यायालय ने ख०न० 5547 गैर मुमकिन बाड़ा सिवायचक पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा अवैध निर्माण होना माना है परन्तु प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने के संबंध में कोई विवेचन नहीं किया है। अपीलार्थी का दावा प्रतिवादी न० 1 व 2 के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर सरकारी भूमि से बेदखल कराने का था परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी को अधिकार नहीं होना अंकित कर दावा खारिज कर दिया। सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर सरकारी भूमि को हड़पना है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। विवादित आराजीयात ख०न० 5547 वादीगण की खातेदारी भूमि से लगती हुई है प्रतिवादीगण उक्त अवैध अतिक्रमण कर वादी को खातेदारी की भूमि में काश्त करने में व्यवधान डालेगा। जिससे भविष्य में विवाद उत्पन्न होने की प्रबल संभावना है। अपीलांट को कोरोना काल में अधिनस्थ न्यायालय में सुनवाई का अवसर ही प्रदान नहीं किया इस कारण भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पों संख्या 3 को आदेश दिये जावे कि रेस्पों संख्या 1 व 2 द्वारा किये गये अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जावे।


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

रेसपो0 के अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अपील के मद संख्या 1 ता 8 को अस्वीकार करते हुए अपील के मद संख्या 8 से 11 का रेसपो0 का कोई संबंध नहीं होना तथा मद न0 12 अपील में किये गये निवेदन को गलत होने से अस्वीकार करते हुए विशेष विवरण में अंकित किया कि विवादित भूमि ख0न0 5547 रकबा 0.99 है0 गैर मुमकिन खरडा है जो पूर्णरूप से सिवायचक है। जिस पर रेसपो0 का पूर्वजो के समय से ही कब्जा चला आ रहा है। रेसपो0 ही को धरणा से पेनल्टी भरते चले आ रहे है। रेसपो0 ने अपीलांट को उनके हिस्से का आधा बाडा दे इसके अलावा 5 फीट जमीन ज्यादा दे रखी है रेसपो0 के अलावा 50 फीट से अधिक गभग आधा गांव सिवायचक भूमि मे बने व बसा हुआ है। प्रशासन पहले तो 50 मकानो को ध्वस्त करे। अपीलार्थी हमारे कब्जा शुदा बाडे के पीछे पडे हुए है वे प्रशासन से कब्जा ध्वस्त करवाकर कब्जा स्वयं करने पर आमादा है। उक्त भूमि सिवायचक है इस कारण अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन निर्णय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात भूमि ख0न0 5547 रकबा 0.99 है0 मुताबिक राजस्व रिकार्ड गैर मुमकिन खरडा सिवायचक दर्ज है। वादी द्वारा गैर मुमकिन भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल करने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसका उसको कोई अधिकार प्राप्त नहीं होने एवं भूमि सिवायचक होने के कारण प्रतिवादीगण के विरुद्ध धारा 91 की कार्यवाही करने के आदेश अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार मलारना डूंगर को दिये गये है। इस प्रकार अपीलांट/वादी विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार नहीं होने से प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी नहीं है। सिवायचक भूमि पर हो रहे अतिचार के विरुद्ध धारा 91 के तहत कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार अधिकृत है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के द्वारा किये गये अतिचार के बाबत धारा 91 की कार्यवाही हेतु विधि अनुरूप ही निर्देशित किया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विधि अनुरूप होने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतः अपीलांट की अपील खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर मलारना डूंगर के मु0न0 61/19 निर्णय व डिक्री दिनांक 13.1.22 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 02.12.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


(लक्ष्मी कांत बालोत)
रजिस्टर अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर